आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा- प्र.मंत्री मोदी

शंघाई को -ऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्र.मंत्री मोदी ने कहा, जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं उन्हें स्पष्ट संदेश देना होगा कि आतंकवाद रणनीतिक ''एसैट'' नहीं हो सकता है

- प्र.मंत्री ने कहा भारत बाजारों को जोड़ने वाले प्रयासों का समर्थन करता है, क्योंकि इससे विकास के नए रास्ते खुलते हैं।

बिश्केक, 01 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और एकजुट कार्रवाई का आ ान करते हुए कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती और जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री ने एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 26वें शिखर सम्मेलन में कहा कि पिछले 25 वर्षों में संगठन ने यूरेशिया के विशाल भूभाग में संवाद और सहयोग की मजबूत परंपरा विकसित की है तथा मानवता के विकास और अपने लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगले 25 वर्षों में इस सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना एससीओ का लक्ष्य होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और सुरक्षा इस दिशा में पहली आवश्यकता है। आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके खिलाफ लड़ाई को केवल कार्रवाही-प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को खत्म करना होगा। जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं और आतंकियों को पनाह तथा समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में सुरक्षा की परिधि और व्यापक हो गई है। पश्चिम एशिया के संकट ने दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र का संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ता है।

उन्होंने दोहराया कि सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्धक्षेत्र में नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है।

एससीओ के दूसरे स्तंभ कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि, ऐसे प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह एससीओ चार्टर की मूल भावना भी है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में कनेक्टिविटी का स्वरूप और व्यापक होगा। सड़कों, रेलवे और हवाई गलियारों के साथ-साथ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल दस्तावेजीकरण को बढ़ ावा देने और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देना होगा।

शक्ति शर्मा भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल बनीं

नई दिल्ली, 01 सितंबर। भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। वह भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल या उसके समकक्ष रैंक हासिल करने वाली पहली गैर-चिकित्सा महिला अधिकारी बन गई हैं। 1 सितंबर 2026 को उन्होंने एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) का पद संभाला। शक्ति शर्मा की यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ ती भूमिका को दिखाती है। तीन दशक से ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने वायुसेना के अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रक्षा से जुड़े कई संस्थागत कार्यों में योगदान दिया है। एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन मिला था। इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर हेडक्वार्टर सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर जिम्मेदारियां संभालीं।

- उन्होंने एक सितम्बर को एयर हैडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (एजुकेशन) का पद संभाला।

जब व्यक्ति लोगों को जोड़ता है, कुर्सी अपने आप उसके पास आती है- पायलट

सचिन पायलट ने मालानी रत्न, गोरधन राम कड़वासरा की प्रतिमा का अनावरण किया

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को बालोतरा जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत अणदाणियों की ढाणी में मालानी रत्न, स्वर्गीय गोरधन राम कड़वासरा की प्रतिमा का अनावरण किया।

बालोतरा/जालोर, 1 सितम्बर। बालोतरा जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत अणदाणियों की ढाणी में मालानी रत्न, स्वर्गीय गोरधन राम कड़वासरा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित, क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं अनेक लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय गोरधन राम कड़वासरा के सामाजिक योगदान और उनके व्यक्तित्व को याद किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि गोवर्धनराम जी के जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कुर्सी के पीछे भागने के बजाय, लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। जब व्यक्ति लोगों को जोड़ता है तो कुर्सी अपने आप उसके पास आती है।

पायलट ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता ने राम मंदिर निर्माण में एक-एक रुपये का सहयोग दिया, लेकिन भाजपा नेताओं ने उस पैसे में चोरी की।

- पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाड़मेर दौरे के दौरान ''वीरेन्द्र धाम'' परिसर में रह रहे छात्रों के साथ नाश्ता किया और उनके अध्ययन व भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली।

इस अवसर पर पूर्व गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी ने स्वर्गीय गोरधन राम कड़वासरा के साथ अपनी दोस्ती और पुराने संबंधों को याद किया। संस्मरण सुनाते हुए वे भावुक हो गए। उन्होंने गोवर्धनराम जी के सरल स्वभाव, सामाजिक सरोकार और लोगों के प्रति उनके जुड़ाव को याद किया।

बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि गोरधन राम कड़वासरा और हेमाराम चौधरी ने कभी लोगों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं जोड़ा, बल्कि जनहित और समाज के लिए काम किया।

इनके अलावा, कार्यक्रम में सांचौर के पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई, पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए।

सचिन पायलट ने मंगलवार को बाड़मेर दौरे के दौरान 'वीरेन्द्र धाम' में विद्यार्थियों से मुलाकात की। पायलट ने धाम परिसर में रह रहे छात्रों के साथ सुबह का नाश्ता किया और उनके अध्ययन और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर पायलट ने वीरेन्द्र धाम द्वारा क्षेत्र के युवाओं के लिए किए जा रहे सामाजिक व शैक्षिणक प्रयासों की सराहना की।

वीरेन्द्र धाम का निर्माण पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने अपने दिवंगत पुत्र स्व. वीरेन्द्र चौधरी की स्मृति में कराया है। यह धाम बाड़मेर में ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास, अध्ययन और मार्गदर्शन का एक प्रमुख केन्द्र बना हुआ है।

ममता बनर्जी की भतीजी का घर पर फंदे से लटका शव मिला

- प्रारंभिक जांच में पुलिस आत्महत्या की आशंका बता रही है।

कोलकाता, 01 सितंबर। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की मंगलवार को बीरभूम जिले में उनके घर पर मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई है। बृष्टि की उम्र 28 वर्ष थी।

पुलिस के अनुसार, रामपुरहाट क्षेत्र के कुसुम्बा गांव स्थित उनके घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे से दोपहर में उनका शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रक्रियात्मक जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, बृष्टि तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थीं। उनका पिछले कुछ वर्षों से अवसाद का इलाज भी चल रहा था। बृष्टि के पिता निहार मुखर्जी, ममता बनर्जी के मामा के बेटे हैं और स्थानीय स्तर पर टीएमसी नेता हैं। मामले में पुलिस की जांच जारी है।

सीजेपी 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को देखते हुए, सीजेपी 5 सितंबर के मार्च का आ ान वापस लेना उचित समझती है और आज के आदेश के अनुपालन की प्रतीक्षा करेगी।'' 24 अगस्त को सीजेपी ने घोषणा की थी कि सरकार द्वारा 25 जुलाई को किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाली जायेगी।

महाराष्ट्र और दिल्ली की एसआईआर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दर्ज किया गया, जबकि 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम इस स्तर पर सूची से बाहर कर दिये गये। कांग्रेस नेता ने मतदाताओं की संख्या में आई इस भारी गिरावट पर सवाल उठाते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पर संदेह जताया। राहुल गांधी ने बंगाल में हुए एसआईआर के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई के बाद, मसौदा सूची से हटाए गए करीब 91 प्रतिशत नाम दोबारा शामिल कर लिए गए थे। उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया, ''इसका मतलब है कि हर 10 में से 9 नाम गलत तरीके से हटाए गए और चुनाव के बाद ही वापस जोड़े गए। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं: यह वोट चोरी थी।''

केजरीवाल ने दिल्ली के बारे में कहा कि करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख नाम गायब हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग 50 प्रतिशत मतदाता चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, ''भारत सरकार आबादी को लेकर बेवजह चिंतित है। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग हमारे देश की आबादी को 140 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर देगा।''

एसआईआर शुरू होने से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। मसौदा मतदाता सूची में करीब 97.54 लाख नाम हैं। इस तरह 47.7 लाख मतदाता, यानी पहले के कुल मतदाताओं में लगभग एक-तिहाई, इस चरण में सूची से बाहर हो गए हैं।

चुनाव आयोग ने दिल्ली के एसआईआर से पहले के 29.86 प्रतिशत मतदाताओं को ''अनुपस्थित/स्थायी रूप से स्थानांतरित/अन्य श्रेणी में रखा है। वहीं, 1.95 प्रतिशत को मृत और 0.98 प्रतिशत को किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत बताया गया है।

पिछले सप्ताह कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि कम गणना दर, दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं या जवाब देने के लिए पर्याप्त समय न मिलने के कारण पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं।

भीलवाड़ा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रत्याशियों का पैनल तय होने के बावजूद ऐन वक्त पर केवल 53 सिंबल ही निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए। उन्होंने कहा 17 प्रत्याशियों के सिंबल रोके जाना प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने जैसा है। पालीवाल ने ज्ञापन के माध्यम से आलाकमान से मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय स्तर की जांच कमेटी गठित कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष दायित्व में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास बहाल हो सके।

नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की एफआईआर रद्द- सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 के तहत दिल्ली और चार राज्यों में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करी

- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि नीट प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को तीन माह में मुआवजा दे दिया जायेगा।

नई दिल्ला, 01 सितंबर। नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिले अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली और चार राज्यों में दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) ने केंद्र के कदम और कोर्ट के आदेश को देखते हुए पांच सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा असम, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में नीट प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। ये मामले 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शन से जुड़े थे। दिल्ली पुलिस और चार राज्य सरकारों ने कोर्ट से आर्टिकल 142 के तहत इन मामलों को खत्म करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले पर सुनवाई की और एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत में दिए गए भरोसे पर कायम है। उन्होंने बताया कि नीट प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने इसके लिए तीन महीने का समय मांगा है।

पाँच साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में तैनात तत्कालीन एएसआई ललिता शर्मा दुर्घटनाग्रस्त हुई मोटरसाइकिल को छोड़ने तथा दुर्घटना करने वाले वाहन को जब्त करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रही हैं। शिकायत का सत्यापन करने पर एएसआई की ओर से दो हजार रुपए की रिश्वत मांगने और सत्यापन के दौरान पांच सौ रुपए लेने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि कार्रवाई के दौरान फैनोफ्थान पाउडर लगी पन्द्रह सौ रुपए की रिश्वत राशि उसके कब्जे से नहीं मिली। जिससे साबित है कि उसने रिश्वत नहीं ली थी। इसका जवाब देते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि भले की ट्रैप के समय रिश्वत राशि बरामद नहीं हो, लेकिन सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग और आंशिक राशि स्वीकार करना प्रमाणित है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सोना नहीं खरीदने और विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी

प्रधानमंत्री मोदी ने इकॉनमी में 7.8 प्रतिशत ग्रोथ पर खुशी जताते हुए स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया

- प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में कहा, विश्व संकटों से घिरा है, सप्लाई चेन बाधित है, फिर भी भारत ने अच्छी प्रगति की है।

नई दिल्ली, 01 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8 प्रतिशत वृद्धि पर देशवासियों को बधाई देते हुए मंगलवार को विकास की गति बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर देने की अपील की। उन्होंने लोगों से गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं, विदेश में शादियों और आवश्यकता नहीं होने पर सोना खरीदने से बचने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि दुनिया युद्ध में डूबी हुई है। विश्व संकटों से घिरा हुआ है और सप्लाई चेन बाधित है, बावजूद इसके, भारत ने अच्छी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से दुनिया में स्थिरता नहीं रही, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों, इरादों और लोगों की ताकत के बल पर बेहतर प्रदर्शन किया है।

मोदी ने देश की तरक्की को लेकर निराशा फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, देश के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे लोग चारों ओर 'झूठ की गूंज' फैलाने में लगे हैं। इस सब चुनौतियों के बावजूद भारत ने 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी विकास की गति को बनाए रखना है और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने देशवासियों से 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को और मजबूत करने तथा स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि यदि विदेश यात्रा केवल घूमने-फिरने के लिए की जा रही है तो उससे बचना चाहिए। इसी तरह विदेश में शादी करने से भी बचना चाहिए। जब तक आवश्यक न हो, तब तक सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक उचित तस्वीर पेश करते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो अपेक्षाकृत युवा आबादी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और ये लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि उनके सामूहिक प्रयास अर्थव्यवस्था के कुल आकार को बढ़ा रहे हैं।

दूसरे देशों के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू खपत से ताकत मिल रही है और वही इसे आगे भी बढ़ा रही है। लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का एक बढ़ता हिस्सा घरेलू स्रोतों से आ रहा है। उदाहरण के लिए कारों को लें। कारों की बिक्री बढ़ी है और इनका उत्पादन मुख्य रूप से देश के भीतर ही होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रभाव बहुत व्यापक है। इसके कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों से लेकर टायर बनाने वालों और सड़क किनारे के गैराज तक, इस पूरी गतिविधि में बहुत से लोग और कारोबार शामिल होते हैं और उनकी आय बढ़ती है।

कारों की बिक्री इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पिछले दशक में, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई ''गोल्डन क्वाड्रिलेटरल'' योजना की घोषणा के बाद देश की सड़कों और राजमार्गों में काफी सुधार हुआ है। इसके बाद से नैशनल हाइवेज़ का विस्तार हुआ है और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। जिसने भी हमारे राजमार्गों पर कार से यात्रा की है, वह इसकी पुष्टि कर सकता है।

जीडीपी के आंकड़ों पर टिप्पणी करने वाले सभी लोगों ने हाल ही में सार्वजनिक निवेश (पब्लिक इन्वैस्टमैंट) के स्तर की ओर इशारा किया है। एक बार फिर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सार्वजनिक निवेश, जैसे बेहतर सड़कों का निर्माण, पुल बनाना और बेहतर गुणवत्ता वाले रेलवे कनैक्शन बिछाना, देश भर में आवाजाही को तेज करता है और सीधे तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।

इस बात को मानने का कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक ऐसे सकारात्मक चक्र पर चल रही है, जिसमें, बुनियादी आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इन्वैस्टमैंट, देश के भीतर बेहतर आवाजाही, बढ़ती आय और बढ़ते उपभोक्ता खर्च एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। आयकर में छूट की सीमा में बड़ी बढ़ोतरी और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का, निश्चित रूप से उपभोक्ताओं की कुल मांग पर असर पड़ा है। बिस्कुट के एक पैकेट से लेकर फ्रिज या कार जैसी बड़ी चीज़ों तक, हर चीज पर अधिक खर्च करने की क्षमता (डिस्पोज़ेबल इन्कम) से उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। बेहतर मांग से निजी क्षेत्र की उन कंपनियों में निवेश भी बढ़ता है, जो ये उत्पाद बनाती हैं।

इस गति को बनाए रखना जरूरी है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। नोटबंदी जैसा कोई और गलत कदम मांग की इस रफ्तार को खत्म कर सकता है। इसी तरह, टैक्स बढ़ाने का कोई भी कदम आर्थिक लाभ के इस सुनहरे मौके को भी खत्म कर सकता है।

मौजूदा स्थिति ''गोल्डीलॉक्स मोमैंट'' (एक आदर्श स्थिति) जैसी है, यानी ऐसी स्थिति, जिसमें अर्थव्यवस्था के लिए परिस्थितियां फिलहाल सही बनी हुई हैं। इसलिए अभी अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक गति में कोई रूकावट नहीं डालना जरूरी है। यह विकास सरकार की, अर्थव्यवस्था को संभालने की समझदारी का नतीजा नहीं है। यह विकास हम भारतीयों की खुद को बेहतर बनाने की व्यक्तिगत कोशिशों का मिला-जुला असर है। सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।

भिवाड़ी में 4 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि कार्रवाही के दौरान जिन कंपनियों की दवाइयां मिली हैं, उनके संबंध में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के औषधि प्रशासन को जानकारी दी गई है, ताकि वहां भी संबंधित कंपनियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आगे की जांच के लिए संबंधित राज्यों में औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम भेजी गई है। यह कार्रवाई औषधि नियंत्रक अजय फाटक के निर्देशन में सुभाष मुटनेजा, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुक्तालय मुख्यालय, महेन्द्र जोनवाल, सहायक औषधि नियंत्रक अलवर, रामकेश मीणा, सहायक औषधि नियंत्रक दौसा एवं अलवर सहित, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम द्वारा की गई।

'डॉक्टरों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हमलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने संकेत दिया कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के 18 जुलाई के उस आदेश को बरकरार रखने के पक्ष में है, जिसमें कल्याण-डोंबिवली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल में तीन डॉक्टरों से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश सुकर्या म्हात्रे को दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ म्हात्रे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 18 जुलाई के जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश और 7 अगस्त के कड़ी जमानत शर्तें लगाने वाले आदेश को चुनौती दी थी।

ये आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा म्हात्रे और उनके सहयोगियों को जमानत दिए जाने के बाद शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही के तहत पारित किए गए थे।

पीठ ने चिकित्सा कर्मियों पर हमले को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि जो लोग डॉक्टरों पर हमला करते हैं, वे जमानत के हकदार नहीं हैं।

हनी ट्रैप मॉड्यूल के लिए छोटे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की संभावना नहीं है। इसके बजाय उसकी नजर छोटे शहरों और गांवों पर है, जहां कम निगरानी के बीच लोगों की भर्ती की जा सकती है और उन्हें आर्थिक प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया जा सकता है।

अधिकारी के अनुसार, आईएसआई ने पहले मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में लोगों की भर्ती की थी, जो फरीदकोट स्थित हैंडलरों को रिपोर्ट करते थे। अब एजेंसी दक्षिण भारत के शहरों में भी अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रही है।

हालांकि, ध्यान छोटे इलाकों पर ही रहेगा, जहां संभावित लोगों को आसानी से भर्ती किया जा सके और उन्हें बड़ी रकम का लालच दिया जा सके।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हाल की जांच में सामने आया है कि आईएसआई ने लोगों को फंसाने और संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए अश्लील सामग्री और नग्नता का इस्तेमाल भी हनी-ट्रैपिंग के तरीकों के रूप में किया।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने आकर्षक महिलाओं के जरिए लक्ष्यों से संपर्क स्थापित किया और खास तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की।

अब एआई ने ऐसे अभियानों का पता लगाना और मुश्किल बना दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, आईएसआई, एआई से तैयार महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो बनाकर संभावित लक्ष्यों से संपर्क स्थापित कर सकती है।

इससे जांचकर्ताओं के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कुछ मामलों में तस्वीरों या वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वास्तव में मौजूद ही नहीं हो सकता। इससे आरोपियों की पहचान करना और पूरे अभियान के स्रोत तक पहुंचना अधिक कठिन हो जाता है।

हनी-ट्रैप नेटवर्क के विस्तार के बीच भारतीय एजेंसियां पहले से ही बड़ी संख्या में ऐसे मामलों से निपट रही हैं। हालिया खुफिया सूचनाओं से यह भी संकेत मिला है कि आईएसआई ने हाल ही में नियुक्त किए गए अग्निवीरों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

अधिकारियों का मानना है कि ऐसे नए भर्ती हुए जवान ऑनलाइन हेरफेर के अत्याधुनिक तरीकों को पहचानने के मामले में अपेक्षाकृत कम जागरूकता के कारण आसानी से निशाना बन सकते हैं।

वे फर्जी तस्वीरों या वीडियो के जाल में फंस सकते हैं और वास्तविक तथा कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री के बीच आसानी से अन्तर नहीं कर पाते।

अधिकारियों के अनुसार, आईएसआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित जानकारी हासिल करना है। ऐसी जानकारी का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के दौरान बढ़त हासिल करने या भारतीय सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हनी-ट्रैपिंग के मामलों में तेज वृद्धि हुई है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस अभियान ने पाकिस्तान के व्यापक समर्थन नेटवर्क को उजागर किया और उसकी परमाणु धमकियों को भी चुनौती दी।

एक अधिकारी ने कहा, ''पाकिस्तानी पूरी तरह बदला लेने पर आमादा हैं और इसलिए ये हनी-ट्रैपिंग अभियान दस गुना तक बढ़ गए हैं, ताकि भारतीय सशस्त्र बलों को बदनाम किया जा सके।''

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908